Important News: International

1. इंटरनेट शटडाउन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों:

- इंटरनेट शटडाउन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होते है तथा सूचना प्रवाह में बाधा आती है साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है।

प्रमुख बिंदु:

- इंटरनेट शटडाउन एक सरकार द्वारा या सरकार की ओर से किए गए ऐसे उपाय हैं, जो सोच समझकर ऑनलाइन सूचना और संचार प्रणालियों के उपयोग को बाधित करते हैं।
- KeepItOn गठबंधन के अनुसार, 2016-2021 तक 74 देशों में 931 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा भी 106 बार इंटरनेट कनेक्शन को अवरुद्ध या बाधित किया गया जिसमें से भारत के कम से कम 85 बार इंटरनेट शटडाउन जम्मू और कश्मीर में किया गया हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-2021 तक इंटरनेट शटडाउन का मुख्य कारण नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किए गए सभी इंटरनेट शटडाउन में से लगभग आधे सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शिकायतों से संबंधित विरोध और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किए गए थे।

स्रोत: द हिंदू

2. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन: 'ब्लू डील'

चर्चा में क्यों:

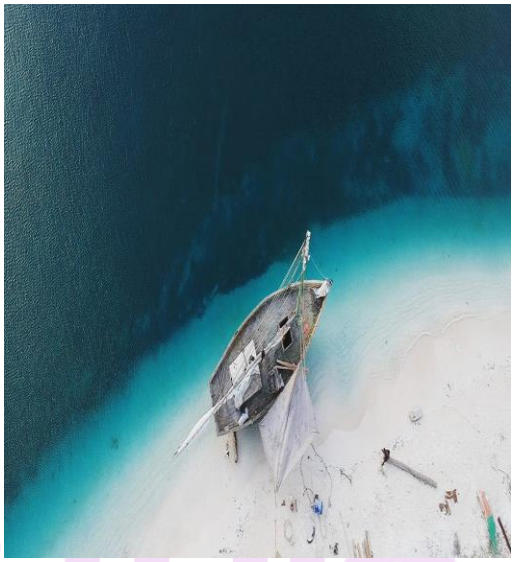

- आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में एक "ब्लू डील" को अपनाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, ब्लू डील में वैश्विक व्यापार, निवेश और एक स्थायी और महासागर अर्थव्यवस्था को आसान बनाने के लिए नवाचार को शामिल किया गया हैं।
- ब्लू डील का मुख्य लक्ष्य तटीय और द्वीपीय विकासशील राष्ट्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, समुद्री परिवहन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों सहित महासागर अर्थव्यवस्था के सतत विकास से लाभ उठाना हैं।
- ब्लू डील विकासशील देशो के लिए रोजगार के साधन उत्पन्न करने में भी सहायक होगा जिसकी सहायता से इन देशों के लिए राजस्व उत्पन्न करने के साधनो में वृद्धि होगी।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

Important News: India

3. 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों:

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिल्ली में आयोजित 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम में भाग लिया गया।

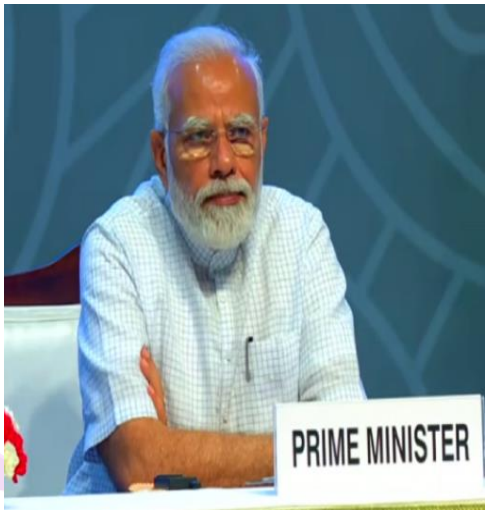

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री द्वारा आयोजन के दौरान 'एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार तथा तेजी' (रैंप) योजना, 'पहली बार के एमएसएमई निर्यातकों का क्षमता निर्माण' (सीबीएफटीई) योजना और 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) की नई सुविधाओं जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी किया गया।
- 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी हस्तांतरित की साथ ही एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 2022 के परिणाम घोषित किए तथा राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, 2022 वितरित किए गए।
- एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 2022 का उद्देश्य व्यक्तियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना, एमएसएमई के बीच नवीनतम तकनीकों को अपनाना तथा नवाचार को बढ़ावा देना है।

स्रोत: पीआईबी

Important News: State

4. औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर

चर्चा में क्यों:

- उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल द्वारा औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर शंभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

प्रमुख बिंदु:

- औरंगाबाद की स्थापना 1610 में अहमदनगर के निजामशाही वंश के सिद्दी सेनापति मलिक अंबर द्वारा की गयी थी,उस समय शहर का नाम खिरकी या खड़की रखा गया था।
- मलिक अंबर के बेटे फतेह खान ने वर्ष 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद औरंगाबाद शहर का नाम फतेहपुर में बदल दिया था।
- वर्ष 1653 में, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा दक्कन पर आक्रमण किया गया औरंगाबाद शहर में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसका नाम औरंगजेब ने औरंगाबाद रखा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Important News: Economy

5. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020

चर्चा में क्यों:

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-बीआरएपी 2020 जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020 में व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर शीर्ष उपलब्धि वाले सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु) की पहचान की गई है।
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2020 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को रखा गया है, जबकि असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आकांक्षी राज्यों श्रेणी में रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा को उभरते हुए बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का उद्देश्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यविधियों से परस्पर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार के अवसर में सुधार लाना है।

स्रोत: बिजनेस टाइम्स

Important News: Science & Technology

6. नासा का कैपस्टोन मिशन

चर्चा में क्यों:

- NASA द्वारा कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु:

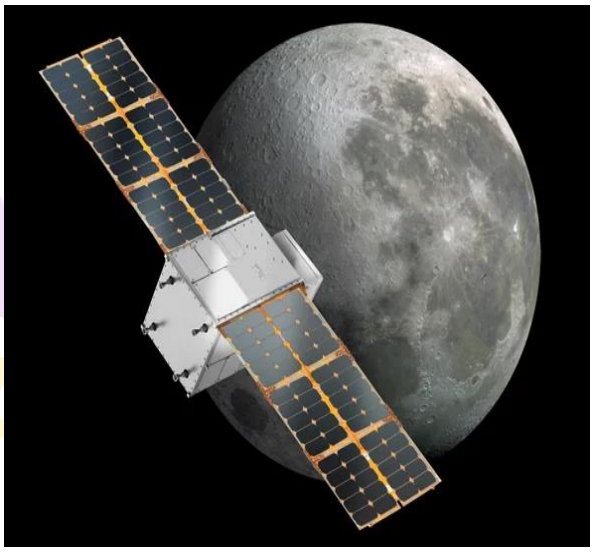

- कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूबसैट है, जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड (25 किलोग्राम) है।
- कैपस्टोन - सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, एक अद्वितीय, अण्डाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे निकट-रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट (NRHO) के रूप में जाना जाता है।
- CAPS (सिसलुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम) कैपस्टोन का एक स्वायत्त नेविगेशन सॉफ्टवेयर है।
- यदि CAPS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है, तो यह सॉफ्टवेयर भविष्य के अंतरिक्ष यान को विशेष रूप से पृथ्वी-आधारित ट्रैकिंग पर भरोसा किए बिना उनके स्थान का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करेगा।

स्रोत: लाइवमिंट

Important News: Appointment

7. न्यायमूर्ति श्री आलोक अराधे

- केंद्र सरकार द्वारा 3 जुलाई, 2022 से प्रभावी, कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आलोक अराधे की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गयी है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आलोक अराधे को इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है।
- यह नियुक्ति, न्यायमूर्ति श्री रितु राज अवस्थी, मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के आलोक में की गयी है, जो 03.07.2022 से प्रभावी होगी।
- न्यायमूर्ति अराधे का जन्म 1964 में रायपुर में हुआ था तथा न्यायमूर्ति अराधे को वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और वर्ष 2011 में उन्हें न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था।

स्रोत: पीआईबी

8. एकनाथ शिंदे

- एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की जबकि भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
- एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र राज्य के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं।
- एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हिंदू मराठा परिवार हुआ था।
- एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी-पंचपखाड़ी सीट से वर्ष 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे, एकनाथ शिंदे इसके बाद वर्ष 2009, 2014 और 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए।

स्रोत: पीआईबी